डिफेंस कारिडोर के दूसरे चरण में 1971 करोड़ का निवेश प्रस्तावित

जसरथपुर और जुलूपुर सिहौर में विकसित हो रहा दूसरा चरण

जागरण संवाददाता, अलीगढ : डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर अपने दूसरे चरण में प्रवेश के लिए तैयार है। भूमि का रास्ता साफ होने के बाद इसमें करीब 1971 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। कंपनियों ने इसके लिए उद्योग विभाग व जिला प्रशासन से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इससे जिले में रोजगार व औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

दूसरे चरण के लिए कोल तहसील के जसरथपुर व जुलूपुर सिहोर गांव में 87.88 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसमें 6.85 हेक्टेयर सरकारी भूमि है व 81.03 हेक्टेयर निजी भूमि है। प्रशासन ने किसानों से सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा तय कर अधिकांश भूमि खरीद ली है। अब तक 80 हेक्टेयर भूमि यूपीडा के नाम दर्ज हो चुकी है। शेष भूमि की खरीद की प्रक्रिया जारी है। विकास कार्यों के लिए पूर्व में भी 65 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे सड़क, नाली, बिजली, पानी व सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। निवेशकों ने भी इस भूमि पर इकाइयां लगाने में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। कई रक्षा उपकरण निर्माण कंपनियों ने यूपीडा से संपर्क कर अपने निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसमें करीब 1971 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इनमें से कुछ कंपनियां जल्द ही जमीन का निरीक्षण करने आ रही हैं।

87.88
हेक्टेयर भूमि पर जल्द ही जमीन पर उतरेंगे विकास परियोजना

81.03
हेक्टेयर निजी भूमि ली जा रही है

6.85
हेक्टेयर इसमें सरकारी भूमि शामिल

65
करोड़ भी विकास कार्यों के लिए स्वीकृत

परियोजना के पहले चरण में कई कंपनियां शुरू

डिफेंस कारिडोर के पहले चरण में खैर तहसील के अडला गांव में 100 हेक्टेयर में विकसित कारिडोर में कई कंपनियां शुरू हो चुकी हैं। यहां भी 1919 करोड़ का निवेश भविष्य में और प्रस्तावित है। यूपीडा के अधिशासी अभियंता एपी सिंह की ओर से इसको लेकर डीएम को पत्र भेजा गया है। इसमें योजना में प्रस्तावित निवेश को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए पांच हजार करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त

- दिसंबर में प्रस्तावित है आयोजन, 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य
- सेरेमनी को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारी, डीएम ने बैठक में की समीक्षा

जागरण संवाददाता, अलीगढ : दिसंबर में प्रस्तावित पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले को 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य मिला है। इसमें से पांच हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें सबसे अधिक कोल्ड स्टोरेज व पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव हैं। फरीदाबाद की कंपनी का सोलर उत्पादन प्लांट का प्रस्ताव भी अहम है। लघु व सूक्ष्म उद्योग से जुड़े प्रस्ताव भी इसमें शामिल किए गए हैं। ख्वाजई में विकसित किए गए प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक आस्थान में रजिस्ट्री शुरू हो गई है।

बुधवार को डीएम संजीव रंजन ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग व व्यापार बंधु की बैठक में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों पर चर्चा की। डीएम ने कहा कि औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन निवेश प्रस्तावों को भूमि, विद्युत, यातायात या अन्य प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। बैठक में बताया गया कि नवीन औद्योगिक आस्थान ख्वाजई में भूखंडों की रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। इसका क्षेत्रफल 116 एकड़ है। एमएसएमई में विकसित प्लेज पार्क के संपर्क मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की जानकारी भी दी गई। डीएम ने कहा कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्य शुरू कराया जाए। निवेश प्रस्तावों की सुचारु प्रक्रिया के लिए डीएम ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को लेकर कड़ा रुख दिखाया।

17 नवंबर तक 43,225 आवेदनों में से 36,787 का समय सीमा में निस्तारण किया गया है। सभी विभाग निर्धारित समयावधि में ही निस्तारण करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार, उद्यमी नेकराम शर्मा, गणेश शेखर शर्मा, चंद्र शेखर शर्मा, बबलू सिंह, कमल गुप्ता मौजूद रहे।

गंदगी और जलभराव की समस्याएं भी उठीं

डीएम ने ताला नगरी व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा, यातायात, जल निकासी व सड़क सुधार के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। व्यापारी नेता सतीश माहेश्वरी ने स्वर्ण जयंती नगर में अतिक्रमण व जिज्ञासु मार्केट में शौचालय का निर्माण पूरा न होने का मुद्दा उठाया। अन्य ने गंदगी व जलभराव की समस्याओं को उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। मीनाक्षी पुल पर यू-टर्न से संबंधित साइनेज बोर्ड लगाने की भी मांग की। अधिकारियों ने लाजिस्टिक योजना में अलीगढ़–रामघाट मार्ग के चौड़ीकरण में ताला नगरी का कार्य भी शामिल करने की जानकारी दी। पारस ज्योति मैरिज होम से आने वाले गंदे पानी की समस्या को तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए।